बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 98 ● नई दिल्ली ● सोमवार 26 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

नारायणा गांव में पार्किंग को लेकर बढ़ा संकट, डीडीए की दीवार बनी मुसीबत

नई दिल्ली । पश्चिमी दिल्ली के नारायणा गांव में रहने वाले लोग इन दिनों पार्किंग की बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं. हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्हें अपने घरों के आसपास वाहन खड़े करने की जगह नहीं मिल रही और मजबूरी में दो किलोमीटर दूर खुले मैदानों में गाड़ियां छोड़नी पड़ रही हैं. ग्रामीणों का कहना है कि घर से इतनी दूरी पर वाहन खड़े करने से न सिर्फ चोरी का खतरा बना रहता है, बल्कि गलत जगह पार्किंग के चलते चालान कटने की आशंका भी बनी रहती है. इस समस्या ने रोजमर्रा की जिंदगी को काफी मुश्किल बना दिया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गांव के पास मौजूद खाली जमीन को अचानक दीवार बनाकर घेर दिया और वहां ताला लगाकर प्रवेश बंद कर दिया. इसी के बाद से पार्किंग की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है.

संभल सीजेएम का तबादला न्यायपालिका पर हमला, ये तानाशाही; कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की?

नई दिल्ली । सम्भल सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि न्यायपालिका की आजादी पर सीधा हमला है। हाल ही में संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया था। यह तबादला ऐसे समय हुआ, जब उन्होंने संभल में हुई हिंसा के मामले में अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार प्रभारी पवन खेड़ा ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट को विभांशु सुधीर के मनमाने तबादले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। खेड़ा ने कहा कि इस मामले में न्यायपालिका को दखल देना चाहिए ताकि देश में कानून का शासन, संस्थाओं की स्वायत्ता और प्रशासन में लोकतंत्र बना रहे। पवन खेड़ा ने दावा किया भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक फायदे के लिए न्यायपालिका पर व्यवस्थागत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही तबादलों को हथियार बनाकर न्यायपालिका की आजादी को नियंत्रित करने वाला तानाशाही एजेंडा लागू करने की कोशिश की जा रही है। संभल सीजेएम के तबादले पर कांग्रेस की नाराजगी वकीलों के विरोध के बाद सामने आई है। दरअसल सीजेएम विभांशु सुधीर के

तबादले के खिलाफ संभल के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया था। वकीलों ने आरोप लगाया था कि न्यायपालिका की आजादी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। संभल हिंसा मामले में संभल सीजेएम विभांशु सुधीर ने बीती 9 जनवरी को तत्कालीन सर्किल अफसर अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर करने का आदेश दिया था। जिसके बाद विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया। पवन खेड़ा ने कहा, विभांशु सुधीर का ट्रांसफर आगरा से सम्भल में 18 सितंबर, 2025 को ही हुआ था। चार महीने के भीतर उनका ट्रांसफर न केवल अभूतपूर्व है, बल्कि यह राजनीतिक हस्तक्षेप, बदले की भावना और संस्थागत दबाव की ओर इशारा करता है। पवन खेड़ा ने कहा, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुधीर का अचानक ट्रांसफर कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, यह संस्थागत दबाव की सोची-समझी कार्रवाई है और यह न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा ने एक खतरनाक और सनकी राजनीतिक फॉर्मूला अपनाया है- साम्प्रदायिक तनाव पैदा करो, सरकारी हिंसा फैलाओ, अपराधियों को बचाओ और फिर जो संस्था जो जवाबदेही की मांग करने की हिम्मत करे, उसे कुचल दो । संभल कोई अपवाद नहीं है, बल्कि यह इस जानबूझकर और खतरनाक रणनीति का नया शिकार है। खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा, हम भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि वे संभल के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विभान्शु सुधीर के मनमाने और बहुत परेशान करने वाले ट्रांसफर का खुद संज्ञान लें। यह मामला सिर्फ एक न्यायिक अधिकारी के ट्रांसफर से कहीं ज्यादा बड़ा है, यह न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संवैधानिक संतुलन की जड़ पर हमला है।

कोर्ट ने बहस के लिए जांच एजेंसी को दिया समय, जारी किया निर्देश; क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा

नई दिल्ली । राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर बहस करने के लिए ईडी को समय दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े एक ईडी मामले में वाड्रा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने मामले के उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट फाइल न करने पर ईडी को फटकार लगाई, जिन पर भरोसा नहीं किया गया था। कोर्ट ने ईडी को अगली सुनवाई की तारीख तक डॉक्यूमेंट्स फाइल करने का निर्देश दिया है। बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है। टाइमिंग ही सब कुछ बता देती है। जब भी पार्लियामेंट खुलने वाली होती है और सरकार से विपक्ष के उठाए गए मुश्किल सवालों के जवाब देने की उम्मीद होती है, तो असली, मुश्किल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया जाता है। संजय भंडारी एक हथियार डीलर है जो 2016 में दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के बाद लंदन भाग गए थे। हाल ही में एक ब्रिटिश अदालत ने भारत सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें भंडारी के प्रत्यर्पण से जुड़े मामले को ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की अनुमति मांगी गई थी। इसके बाद भंडारी को भारत लाने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। ईडी ने 2023 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।

मुठभेड़ के बाद शातिर झपटमार गिरफ्तार, आधी रात को चली गोलियां; चार वारदातों को दिया था अंजाम

नई दिल्ली । दिल्ली में एक बार फिर मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जहां साउथ ईस्ट जिले में गोलीबारी के बाद एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। जिसका नाम सतीश भाटी (22) बताया जा रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर गोली चलाई थी, लेकिन टीम ने उसे काबू कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक पिस्टल, एक मोटरसाइकिल और छह छीने गए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, सतीश भाटी एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि भाटी और उसके एक साथी ने 22 जनवरी को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में लूट की चार वारदातों को अंजाम दिया था। इन घटनाओं में पुल प्रहलादपुर, कालकाजी, अमर कॉलोनी और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन घटनाओं में मोबाइल फोन छीने गए थे। डीसीपी साउथ ईस्ट हेमंत तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि साउथ ईस्ट जिले के पुलिस पुल प्रहलाद पुर और एएटीएस (एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वाड) की टीम ने एमबी रोड के पास गोलीबारी के बाद आदतन अपराधी सतीश भाटी को पकड़ा है। भाटी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर गोली चलाई थी। लेकिन टीम ने उसे काबू कर लिया। बदमाश के पास से एक पिस्टल, एक मोटरसाइकिल और छह छीने गए/लूटे गए मोबाइल बरामद किए गए हैं। भाटी और उसके एक साथी ने 22 जनवरी को पुलिस स्टेशन कालकाजी, अमर कॉलोनी, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया और पुल प्रहलादपुर के इलाके में छीनने की चार घटनाओं को अंजाम दिया था।

पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया, कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने संसद में पार्टी के घोषित रुख का कभी उल्लंघन नहीं किया. तिरुवनंतपुरम सांसद ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से उनकी एकमात्र सार्वजनिक असहमति ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थी. थरूर ने केरल साहित्य महोत्सव के एक सत्र के दौरान सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने उस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया था और उन्हें इसका खेद नहीं है. शशि थरूर का यह बयान इन हालिया खबरों के बीच आया है जिनमें थरूर के पार्टी नेतृत्व से मतभेद की बात कही गई है. ऐसी अटकलें हैं कि थरूर इस बात से आहत हैं कि राहुल गांधी ने हाल में कोचि में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर उनके मौजूद होने के बावजूद उनके नाम का उल्लेख नहीं किया और राज्य के नेताओं द्वारा बार-बार उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है.

पहलगाम हमले को लेकर क्या बोले शशि थरूर?

कांग्रेस सांसद ने अपनी बात स्पष्ट

करते हुए कहा कि एक पर्यवेक्षक और लेखक के रूप में उन्होंने पहलगाम घटना के बाद एक अखबार में स्तंभ लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसको सजा मिलनी चाहिए और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ऐसे में उसे पाकिस्तान के साथ लंबे टकराव में नहीं पड़ना चाहिए और कोई भी कार्रवाई आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाने तक सीमित होनी चाहिए.

शशि थरूर ने नेहरू का किया जिक्र

कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि भारत सरकार ने ठीक वही किया जैसा उन्होंने कहा था. थरूर ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही यह प्रश्न किया था कि अगर भारत खत्म हो जाएगा तो कौन जीवित रहेगा? उन्होंने कहा, जब भारत दांव पर हो, जब भारत की सुरक्षा और दुनिया में उसका स्थान दांव पर हो तो भारत पहले आता है.

राष्ट्रहित की बात आए तो भारत सर्वोपरि- थरूर

कांग्रेस सांसद ने कहा कि बेहतर भारत के निर्माण की प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रहित की बात आती है तो भारत को ही सर्वोपरि होना चाहिए.

सादगी, साहस और जनसेवा की अमिट विरासत

राजमाता विजया राजे सिंधिया मिलनसार, स्नेही तथा जनसेवी भावना से ओतप्रोत महिला थीं, साथ ही एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थीं। उनकी जनसेवा का प्रभाव देखें उनके नहीं रहने के बाद भी आज भी कई शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सा संस्थान व समाज उपयोगी कार्य अनवरत उनके आशीर्वाद से चल रहे हैं। अपने निजी जीवन में वे बहुत सादगी पसंद थीं। लेकिन कर्मठता पूर्वक कार्य उन्होंने ताउम्र ऐसा किया कि उन्हें नजदीक से जानने वाले उनकी अनथक कार्यशैली को जानने वाले दांतों तले उँगली दबा लेते थे। राजमाता विजयाराजे सिंधिया का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। उनके पिता ठाकुर ठाकुर महेंद्र सिंह ब्रिटिश हुकूमत में डिप्टी कलेक्टर थे। अल्पावस्था से ही अपने नाना नानी के सानिध्य में रहीं, जिनके संस्कारों से अभिभूत राजमाता पर बहुत गहरा असर पड़ा। एक फरवरी 1969 के चुनाव माहौल में जब अटल बिहारी वाजपेई वाराणसी पहुंचे थे तो बेनिया बाग में आमसभा रखी गई थी, जिसमें राजमाता का भी भाषण था। वे जब बोल चुकीं तब बाजपेयी जी भाषण देने खड़े हुए। उनके संबोधन पश्चात प्रथम संवाद के- कहिये सुना आपने राजमाता का भाषण....! कितना ओज है कितनी वेदना है उनके भाषण में! राजनीति के क्षेत्र में है कोई दूसरा, जो इनके साथ तुलना कर सकें! अपने राजमहल के सब सुख छोड़कर वे आज जनता का दुःख बंटाने निकल पड़ी हैं। अटल जी ने भी राजमाता को हमेशा बड़प्पन और सम्मान दिया, उन्होंने तो उनके ऊपर से लेख भी लिखे हैं। राजमाता का आत्मबल काफी ओजता लिये हुए था। वे कोई भी निर्णय लेने और उसे कार्यरूप में परिणित करने में जरा भी नहीं सकुचाती थीं। जनता के हितों के लिये वे किसी भी खतरे का सामना करने के लिये सदा तैयार रहती थीं। जनहित के लिये कितना भी बड़ा त्याग करने के लिए वे तत्पर रहती थीं। इसका एक उदाहरण है। जब ग्वालियर राय का विलय भारतीय गणराय में हुआ तो उस समय उन्होंने कहा कि हमारा राय खत्म हो रहा है जरूर, अपितु जनता के कल्याण के लिये यदि प्रजातंत्र यादा हितकर है तो उसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। जनता के विकास और कल्याण के लिये ही उन्होंने ने राजनीति में कदम रखा। 1965 के आम चुनाव के बाद का मध्य प्रदेश के महाकौशल और विंध्य के क्षेत्र में सूखे के कारण भयंकर अकाल पड़ा था। सो वहां लोगों का जीवन दूभर हो गया था। जिन लोगों की यह जिम्मेदारी थी कि वे ऐसी विकट परिस्थितियों से वहां की जनता को निजात दिलाने का प्रयास करें। उन ऐसे सत्ताधीश भूखेनंगी जनता के समक्ष जाने की बजाय पचमढ़ी की सुरम्य वादियों पर पिकनिक मना रहे थे। तब ऐसी स्थिति को देखकर राजमाता से रहा नहीं गया। और वे अपने स्वास्थ्य और सुखचैन की चिंता किये बगैर उस सूखे और प्रचंड गर्मी में धुंआधार दौरा किया। जहां वे लोगों के बीच जाकर उनके दुःख दर्द को सुनकर उन्हें दिलासा देतीं और जितना मदद करते बन सका वे अपनी क्षमतानुसार उनके दर्द को कम करने का कार्य किया। राजमाता ने कभी भी कुर्सी का मोह नहीं किया। वे चाहतीं तो कभी की मुख्यमंत्री सहित बड़े पदों पर सुशोभित हो सकती थीं। पर उन्होंने जनसेवा में आने, इसे गौण समझा और यही शैली इन्हें जनता में लोकप्रिय और विजय शालिनी बनाने में हमेशा सहायक सिद्ध होता रहा। उन्होंने हमेशा नारी जाति को स्वावलंबी और उनकी शक्ति को महसूस कराने का कार्य किया। 16 मई 1969 को मध्यप्रदेश के विधान सभा चुनाव में तो उज्जैन की नारियों से एक सभा में कहाकि मैं जानती हूं कि महिलाओं में कार्य करने की असीम शक्ति है इसे आवश्यकता इस बात की है कि वे किसी कार्य का संकल्प धारण कर कार्य में जुटें। समानता के प्रचार का उपयोग कर उन्हें देश सेवा में लग जाना चाहिये। ऐसे कठिन काल में जबकि समाज में नैतिकता, चरित्र और धर्म का लोप होने का समय है, महिलाओं को आगे बढ़कर अपनी संस्कृति, धर्म और देश की परम्पराओं की रक्षा करनी चाहिये। राजमाता के जीवन में हिन्दुत्व के प्रबल पोषक और आजादी के प्रतीक महाराणा प्रताप और शिवाजी के चरित्र का गहरा प्रभाव और बहुत कुछ अनुकरणीय भाव परिलक्षित दिखाई देता है। राजमाता ने राजनीति में प्रवेश कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ किया। और सर्वप्रथम उन्होंने 1962 में ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़ा। जिसमें बहुती भारी मतों से विजयी रहीं। इसी वर्ष वज्राघात स्वरूप उनके पति महाराज का भी निधन हो गया। 1966 आते आते उनका कांग्रेस पार्टी में मोहभंग हो गया और उन्होंने जनसंघ पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया। और जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ तो पार्टी को जन्म देने वाले लोगों में प्रमुख रूप से राजमाता भी शामिल थीं।

साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक और फिल्म में धार्मिक-सांप्रदायिक उन्माद खतरनाक

यदि लेखक, कलाकार अथवा किसी भी रचनात्मक विधा से जुड़ा व्यक्ति कहे कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उसे काम मिलने से पहले इस बात की पड़ताल की जाती है कि वह किस धर्म, सम्प्रदाय, जाति से आता है, तो यह संकेत है कि कुछ लोगों द्वारा समाज में विष घोलने की कोशिश हो रही है। रचना धर्म स्वतंत्र है - साहित्य, संगीत, फिल्म निर्माण जैसे कलाक्षेत्र मूलरूप से मानवीय संवेदनाओं, विविधता और सामाजिक सरोकारों का आइना हैं, जिन्हें सकारात्मक आलोचना से बढ़ावा मिलता है। यदि कुछ इसके विपरीत हो, जिससे धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक तनाव और एक-दूसरे के प्रति घृणा का भाव पैदा हो, तो समाज विभाजन और हुड़दंग का शिकार हो जाता है। जब कोई रचना उसके रचनाकार की व्यक्तिगत कुंठा और द्वेष का परिचय दे तो पाठक और दर्शक वर्ग को सचेत हो जाना चाहिए कि कहीं इसके पीछे कोई विकृत एजेंडा या पूर्वाग्रह तो नहीं है भावनाओं को भड़काकर स्थायी रूप से आपसी मेलजोल, सद्भाव और मिलनसारिता को समाप्त करना तो नहीं है यह स्थिति इतनी खतरनाक है कि इसके शुरू होते ही इस पर अंकुश लगाने के लिए सामान्य नागरिक से लेकर शासन, प्रशासन और सरकार तक को तुरंत आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब कोई लेखक या कला धर्मी यह कहे कि उसे एक धर्म विशेष का होने से भारत में डर लगता है, उसे काम नहीं मिलता और वह असुरक्षित महसूस करता है तो फिर तुरंत जनता को यह जांच-पड़ताल करनी चाहिए कि उसकी बात में सचाई है या मनघड़ंत है और फिर सच का साथ देने और झूठ का नकाब उतारने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सामान्य तौर पर पाठक या दर्शक हर उस कृति की, चाहे पुस्तक हो या फिल्म, नृत्य प्रस्तुति हो या थिएटर में नाटक, प्रशंसा करते हैं जो उनके दिल को छू जाए, दिमाग को झकझोर दे और उसके साथ उनका तादात्म्य यानी लगाव होने लगे। इसके साथ ही यदि कोई प्रस्तुति किसी प्रकार का स्पंदन या उसके साथ जुड़ाव पैदा करने में विफल रहती है तो वह पाठ्य या सिनेमा जगत में चारों खाने चित हो जाती है, मतलब फ्लॉप, जिस पर कोई भी अपना समय और धन खर्च करना नहीं चाहेगा। यदि कुछ ऐसा है जो वास्तव में श्रेष्ठ है, तो चाहे शुरू में उसे अपने प्रशंसक न मिलें लेकिन वह अपनी गुणवत्ता के कारण एक मुंह से दूसरे मुंह तक यानी माऊथ पब्लिसिटी से अपना उचित स्थान प्राप्त कर लेती है। कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता कि इसमें किस धर्म या जाति के लेखकों या कलाकारों ने काम किया है, बस वह पसंद आनी चाहिए। कलाएं तो केवल दर्पण हैं, जिन्हें हम जितना साफ, सुंदर, सजा-संवारकर पेश करेंगे, उन्हें उतना ही पसंद किया जाएगा। इसमें न धर्म आता है, न जाति या कुछ और, केवल सत्य के दर्शन होते हैं। कालजयी होना यही है।

क्या गलत है - किसी एक धर्म को खलनायक, एक झूठ को मनवाने की कोशिश और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर दिखाया जाना आक्रोश से लेकर हुड़दंग तक का माहौल बना सकता है। जिनके स्वार्थ समाज को अस्थिर अर्थात दंगा-फसाद करने से सिद्ध होते हैं, वे कामयाब हो जाते हैं। इसे किसी भी नजरिए से सही नहीं ठहराया जा सकता। धार्मिक-सांप्रदायिक उन्माद जब विभिन्न कलाओं के माध्यम से उभर कर आता है, तो उसके परिणाम विनाशकारी ही हो सकते हैं और इस तरह की ओछी बातें कही जाती हैं कि यदि यहां सुरक्षित नहीं हो तो पाकिस्तान या कहीं और चले जाओ। यह स्थिति विध्वंस की पृष्ठभूमि हो सकती है लेकिन नियति नहीं, जिसे स्वीकार किया जा सके। लेखकों या निर्माताओं को धमकियां, पुस्तक, नाटक, प्रदर्शनी या फिल्म पर प्रतिबंध और फिर पुरस्कार वापसी जैसी स्थितियों से बचा जा सकता है, बशर्ते बिना समय गंवाए समुचित उपाय और सख्त कार्रवाई हो जाए। ऐसे प्रचार-प्रसार पर रोक लगना तो समझ में आता है, जो विविधता को चुनौती देता हो, असहिष्णुता को बढ़ावा और रचनाकार की स्वतंत्रता पर हमलावर हो लेकिन जब ऐसी कृतियों पर पाबंदी लगाई जाए, जो धार्मिक पाखंड को उजागर करती हों, सामाजिक विकृतियों का खुलासा करती हों और किसी भी स्तर पर हुए अत्याचार का विरोध करती हों, उन्हें प्रकाशित और प्रसारित करने पर गैरकानूनी तरीके से प्रतिबंध लगाना हिटलरशाही है।

परिवर्तन ही नियम है - हमारे देश की प्रत्येक भाषा इस दृष्टि से समृद्ध रही है कि उन सभी में एक या अधिक रचनाकार ऐसे हुए और हैं, जो अपनी कृतियों से, लेखन से सिनेमा तक को न केवल प्रभावित करते रहे हैं, बल्कि वे विरासत के रूप में जानी जाती हैं।

विभिन्न देसी और विदेशी भाषाओं में अनूदित या रूपांतरण होना श्रेष्ठता का प्रमाण है। अब क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, जिंदगी का बहाव बिना रुके या थमे चलता रहता है, इसलिए कोई रुकावट उसकी गति को न तो नियंत्रित कर सकती है और न ही रोक या बंदिश लगा सकती है। इसका उदाहरण यह है कि जो आधुनिक टैक्नोलॉजी या नए साधनों का उपयोग करने से हिचकिचाता है, उसे अपनाता नहीं और अपनी पुरानी सोच पर ही कायम रहता है, वह बहुत जल्दी भुला दिया जाता है, चाहे उसने जीवन में कितने ही कीर्तिमान हासिल किए हों। रचनाकार अपनी पुरानी सोच के भरोसे बैठा रहा तो पिछड़ा ही कहलाएगा।

सम्पादकीय...

अमरीकी साम्राज्यवाद का नया युग

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को वेनेजुएला में उनके कार्यों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन, लंबे समय से चले आ रहे मानदंडों की अवहेलना और अन्य देशों, विशेष रूप से डेनमार्क और कनाडा जैसे सहयोगियों के खिलाफ धमकियों के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और आशंका का माहौल छाया हुआ है। परिणाम न तो अमरीका के लिए और न ही शेष विश्व के लिए अच्छे होंगे। हमें अभी भी अमरीकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर की द्वितीय विश्व युद्ध से उभरे औद्योगिक-सैन्य परिसर के बारे में दिलाई चेतावनी याद है। यह अपरिहार्य था कि जिस देश का सैन्य खर्च बाकी दुनिया के संयुक्त सैन्य खर्च के बराबर हो, वह अंततः अपने हथियारों का इस्तेमाल दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए करेगा। राजनीति में आने के बाद से (और शायद उससे पहले भी) उन्होंने खुद को कानून से ऊपर समझा और दावा किया है कि न्यूयॉर्क के फिफ्थ एवेन्यू पर किसी को गोली मारने पर भी उन्हें वोट का नुकसान नहीं होगा। 6 जनवरी, 2021 को अमरीकी कैपिटोल में हुए विद्रोह, जिसकी वर्षगांठ हमने अभी-अभी मनाई है, ने साबित कर दिया कि वह सही थे। 2024 के चुनाव ने रिपब्लिकन पार्टी पर ट्रम्प की पकड़ को और मजबूत कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि पार्टी उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए कुछ नहीं करेगी। वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से गैरकानूनी और असंवैधानिक थी। सैन्य हस्तक्षेप होने के नाते, इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक थी, भले ही वह सूचना न भी हो। और भले ही इसे 'कानून प्रवर्तन' का मामला मान लिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ऐसे मामलों में प्रत्यर्पण अनिवार्य है। कोई भी देश दूसरे देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं कर सकता या विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से राष्ट्राध्यक्षों, को उनके देश से अगवा नहीं कर सकता। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य लोगों पर युद्ध अपराधों के आरोप लगे हैं लेकिन किसी ने भी उन्हें कहीं भी पकड़ने के लिए सेना तैनात करने का प्रस्ताव नहीं रखा। ट्रम्प की बाद की टिप्पणियां और भी अधिक बेशर्मी भरी हैं। उनका दावा है कि उनका प्रशासन वेनेजुएला को 'नियंत्रित' करेगा और उसका तेल छीन लेगा, जिसका अर्थ है कि देश को उच्चतम बोली लगाने वाले को भी तेल बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन दावों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि साम्राज्यवाद का एक नया युग शुरू हो चुका है। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' और बाकी कुछ मायने नहीं रखता। और उन रिपब्लिकनों की ओर से कोई खास विरोध नहीं हुआ, जो कभी गर्व से अमरीकी 'मूल्यों' का बखान करते थे। कई टीकाकारों ने वैश्विक शांति और स्थिरता पर इसके प्रभावों पर पहले ही चर्चा कर ली है। यदि अमरीका पश्चिमी गोलार्ध को अपना प्रभाव क्षेत्र घोषित करता है (डोनरो सिद्धांत) और चीन को वेनेजुएला के तेल तक पहुंचने से रोकता है, तो चीन पूर्वी एशिया पर दावा क्यों न करे और अमरीका को ताइवान के तेल तक पहुंचने से क्यों न रोके ऐसा करने के लिए उसे ताइवान पर शासन करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि केवल उसकी नीतियों को नियंत्रित करना होगा।

साम्राज्यवाद के लुटेरे दौर में आज कोई देश सुरक्षित नहीं

जब सोवियत संघ का पराभव हुआ था, उदारपंथी पूंजीवादी लेखक इसका एलान कर रहे थे कि जनतंत्र की सार्वभौम विजय और स्थिरता का युग आ पहुंचा है। वे समाजवादी चुनौती को अनावश्यक और निरर्थक मानते थे और यह मानते थे कि पूंजीवाद, जो पहले ही अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता दे चुका था तथा सार्वभौम वयस्क मताधिकार एवं उसकी रीढ़ के रूप में कल्याणकारी राज्य के कदमों को ला चुका था, इस चुनौती की गैरमौजूदगी में मानवता के लिए शांति, आर्थिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने जा रहा है। दूसरी ओर, अनेक वामपंथी लेखक थे, जो निरुपनिवेशीकरण और सार्वभौम वयस्क मताधिकार तथा कल्याणकारी राज्य के कदमों के लाए जाने को, पूंजीवाद के हाथों से झपटी गयी ऐसी रियायतों के रूप में देखते थे, जिन्हें उस समय छीना गया था जब पूंजीवाद, समाजवादी चुनौती के चलते अपने अस्तित्व के लिए ही संकट का सामना कर रहा था। इन वामपंथी लेखकों ने यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया था कि इस चुनौती के पीछे हटने से, पूंजीवादी व्यवस्था फिर से अपने सामान्य लुटेरे रूप में आ जाएगी और इन रियायतों को वापस छीन लेगी। ये बाद वाले लेखक ही सही साबित हुए हैं और साम्राज्यवाद ने--यहां हम उसी की बात करेंगे--अपने नग्न तौर पर हमलावर स्वभाव को प्रदर्शित किया है और उस चीज का प्रदर्शन किया है जिसे उसका लुटेरा दौर ही कहा जा सकता है। अमेरिकी साम्राज्यवाद ने क्या किया है उसने एक सैन्य कार्रवाई के जरिए, एक अन्य देश के विधिवत निर्वाचित राष्ट्रपति, वेनेजुएला के निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी को उनके घर से अगवा कर लिया है और उन्हें हथकड़ियां डालकर अमेरिका लाया गया है, जहां उन पर ऐसे फर्जी आरोपों में मुकद्दमा चलाया जा रहा है, जिनके लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य है ही नहीं। और अमेरिका उनके देश पर तब तक सीधे-सीधे अपने उपनिवेश के तौर पर राज करेगा, जब तक कि वह किसी पर्याप्त रूप से अनुकूल सरकार को इस देश पर बैठा नहीं देता है। यह एक अविश्वसनीय धृष्टता की करतूत है, जो अंतरराष्ट्रीय आचरण के सभी कानूनी तथा नैतिक नियमों को पांवों तले रौंदती है और साम्राज्यवाद के इस लुटेरे दौर की ही पहचान कराती है। बहरहाल, यह तो साम्राज्यवाद के लुटेरे दौर की ताजातरीन करतूत भर है। इराक के सद्दाम हुसैन को जबरन सत्ता से हटाया गया तथा फांसी पर लटका दिया गया और वह भी पूरी तरह से फर्जी आरोप लगाकर किया गया। लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी की नृशंसता से हत्या कर दी गयी। सीरिया पर कब्जा कर लिया गया। फिलिस्तीनी जनता का नरसंहार किया गया, जबकि उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसे यह मंजूर नहीं है कि साम्राज्यवाद-समर्थित सैटलर औपनिवेशिक परियोजना के जरिए, उसे अपने घरों से बेदखल कर दिया जाए। गज़ा को एक अमेरिकी उपनिवेश के रूप में हाथ में लिया जा रहा है, जिसका शासन डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुना गया वायसराय संभालेगा और गज़ा को एक बेश कीमती अचल संपत्ति के टुकड़े में तब्दील कर दिया जाएगा। ये सभी साम्राज्यवाद के लुटेरे दौर के उन्मुक्त होने की प्रक्रिया में आए प्रकरण हैं। उदारवादी विचारक अब भी, डोनाल्ड ट्रंप को एक सिरफिरे के रूप में लुटेरे की तरह आचरण करने के लिए जिम्मेदार तो मानते हैं, लेकिन डाल को लुटेरों वाली करतूतों की सारी जिम्मेदारी उसी पर डालते हैं। लेकिन, ऊपर बताए गए प्रकरणों में से अधिकांश तो डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले के हैं। ट्रंप और उससे पहले के अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बीच अंतर यही है कि दूसरे राष्ट्रपतियों ने अपनी लुटेरी करतूतें सभ्य लफ्फाजी के आवरण में छुपाने का काम किया था, जबकि ट्रंप अपने प्रशासन के इरादों को छुपाने की कोई कोशिश नहीं करता है। इसके अलावा, पीछे उल्लेखित प्रकरणों में से हरेक में, और इसमें फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार भी शामिल है, अन्य साम्राज्यवादी देशों का पूरा समर्थन हासिल रहा है, जबकि वे अपने कथित उदारवादी सिद्धांतों का ढोल पीटते कभी नहीं थकते हैं। यहां तक कि निकोलस मादुरो के अपहरण को भी, जिसकी दुनिया भर ने निंदा की है, जिसके अपवाद वैश्विक दक्षिण के गिने-चुने देश ही हैं जो ट्रंप को खुश करना चाहते हैं (जिनमें दुर्भाग्य से भारत भी शामिल है), जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन का सक्रिय या मूक समर्थन हासिल है। खासतौर पर अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों द्वारा एक दलील इस तरह की दी जा रही है कि निकोलस मादुरो तो एक तानाशाह शासक था, इसलिए उसके सत्ता से हटाए जाने पर कोई आंसू नहीं बहाए जाने चाहिए। इस दलील का सरासर बेतुकापन साफ देखा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय कानून अमेरिका को और वास्तव में किसी अन्य देश को भी, इसकी इजाजत नहीं देते हैं कि किसी अन्य देश के मामलों में सैन्य हस्तक्षेप करे, जिससे वहां जनतंत्र की स्थापना कर सके। यह तय करना तो संबंधित देश की जनता पर ही है कि उसका शासक कौन होगा। इसलिए, अमेरिकी हस्तक्षेप के संदर्भ में यह तो पूरी तरह से ही अप्रासंगिक है कि मादुरो तानाशाह था या नहीं था। इसके अलावा, ट्रंप को खुद खुलेआम यह स्वीकार कर चुका है कि वेनेजुएला में मादुरो की मुख्य विरोधी, मारिया कोरिना मचाडो को इसके लिए पर्याप्त जनसमर्थन हासिल नहीं है कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वह प्रशासन को संभाल सके। किसी देश में जहां दो राजनीतिक मोर्चे हों, अगर एक को पर्याप्त जनसमर्थन हासिल नहीं है, तो उसके तो यही कहता है कि दूसरे मोर्चे को उससे यादा समर्थन हासिल होगा। ऐसी सूरत में यह दावा करना, जो दावा खुद ट्रंप ने तथा अनेक यूरोपीय नेताओं ने किया है, कि मादुरो को राजनीतिक वैधता हासिल नहीं थी, पूरी तरह से बकवास है। अगर मचाडो को राजनीतिक वैधता हासिल नहीं है और मादुरो को भी हासिल नहीं है, तब ट्रंप को बताना चाहिए कि वेनेजुएला में राजनीतिक वैधता किसे हासिल है मादुरो को हटाने का असली कारण ट्रंप ने अपनी खास उजड्डता के साथ खुद ही बता दिया। शनिवार, 3 जनवरी को अपने संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा- हम बहुत भारी मात्रा में संपदा (वेनेजुएला की) जमीन से निकालने जा रहे हैं। उनका कहना था कि इससे जो पैसा बनेगा वह सिर्फ वेनेजुएला के लोगों के लिए ही नहीं होगा बल्कि अमेरिकी तेल कंपनियों को भी जाएगा और उस देश द्वारा किए गए नुकसानों के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में संयुक्त राय अमेरिका को जाएगा। वह जिन नुकसानों का जिक्र कर रहे थे, ऐसा लगता है कि वेनेजुएला के अपने तेल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करने से हुए कथित नुकसान हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया के दूसरे किसी भी देश से यादा तेल है। उसके संचित तेल भंडार, विश्व के कुल संचित तेल भंडार के 17 फीसद के बराबर बैठेंगे। और वेनेजुएला का तेल लूटने का ट्रंप का प्रस्ताव, सूक्ष्म स्थूल यह कबूल करना है कि इस देश को हथियाने और उसे चलाने का यही मकसद है। यह खुली डकैती के सिवा और कुछ नहीं है। चूंकि तुम्हारे पास तेल है, उसे हम हथिया लेंगे। अगर तुम्हारा राष्ट्रपति इसके आड़े आता है तो हम उसका अपहरण कर लेंगे और उसके बाद तुम्हारे देश को या तो सीधे एक उपनिवेश की तरह चलाएंगे या फिर उसकी जगह किसी कठपुतली सरकार को बैठा देंगे, जो हमें तुम्हारे देश को लूटने का मौका देगी। बेशक, दूसरे देशों के संसाधनों को, जिसमें उनकी जमीन या जमीन से मिलने वाले उत्पाद भी शामिल हैं, लूटने का काम साम्राज्यवाद हमेशा से ही करता आया है। यह तो साम्राज्यवाद के केंद्र में ही है। निरुपनिवेशीकरण के बाद उसने लूट की इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, इस काम में अपने आड़े आने वाली सरकारों का तख्तापलट कराने और उनकी जगह पर अपनी फर्माबरदार सरकारें बैठाने की कोशिश की थी। इसके उदाहरणों के रूप में ग्वाटेमाला में अरबेंज, ईरान में मोसद्देह, कांगो में (तब देश का यही नाम था) लुमुम्बा और चिली के एलेंदे के खिलाफ सीआईए-प्रायोजित तख्तापलटों का नाम खुद ब खुद सामने आ जाता है। और अपेक्षाकृत हाल में पूर्वी-यूरोप तथा पूर्व-सोवियत गणराज्यों में करायी गयी विभिन्न रंगीन क्रांतियां और पश्चिम एशिया पर अमेरिकी हमले भी इसी श्रेणी में आते हैं। इन पहले के तमाम मामलों में और वेनेजुएला के मामले में अंतर इसी तथ्य में निहित है कि जहां पहले के मामलों में अमेरिका यह दिखाने की कोशिश करता था कि वह तो एक आंतरिक टकराव में, एक खास पक्ष का साथ दे रहा था, जबकि पर्दे के पीछे वह तख्तापलट कराने के लिए काम कर रहा होता था, लेकिन वेनेजुएला के मामले में उसने सीधे-सीधे सैन्य हस्तक्षेप किया है और इसके लिए, आंतरिक टकराव के किसी एक पक्ष का समर्थन करने के दिखावे को, तिनके की ओट तक नहीं ली गयी है। बेशक, वह ऐसे देशों को भी अपने हमले का निशाना बनाता है जहां साम्राज्यवाद-विरोधी सरकारें हैं, फिर भले ही ये देश खनिज संपदा के मामले में खास संपन्न न हों। ट्रंप ने कुख्यात मुनरो सिद्धांत को पुनर्जीवित करने की अपनी कोशिश के हिस्से के तौर पर क्यूबा, मैक्सिको तथा कोलंबिया को निशाना बनाने के अपने मंसूबों का एलान भी कर दिया है। लेकिन, उसके साम्राज्य के दायरे में लातीनी अमेरिका तथा कैरीबियाई क्षेत्र ही नहीं आते हैं। अमेरिकी दखलंदाजी से आज तो दुनिया का कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। तथाकथित क्यूबाई मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ ने क्यूबा की हिफाजत की थी, जब अमेरिका ने इस द्वीप देश पर हमले की धमकी दी थी।

अमेरिका के साथ नाभिकीय टकराव भड़कने तक का जोखिम लेकर, तब सोवियत संघ ने क्यूबा की हिफाजत की थी। इसी तरह, इससे भी पहले उसने, मिस्र के नेता नासिर द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद, आंग्ल-फ्रांसीसी हमले के खिलाफ मिस्र की हिफाजत की थी। इन दोनों ही मामलों में साम्राज्यवाद को अपने पांव पीछे खींचने पड़े थे। आज सोवियत संघ की कमी दुनिया के ऐसे सभी देशों को बहुत खलने वाली है, जिनके लिए अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवाद से खतरा है। साम्राज्यवाद का यह लुटेरा दौर, जो साम्राज्यवाद की अब तक की चरम अवस्था है, जाहिर है कि बहुत लंबा नहीं चल सकता है।

राजनीति में युवा नेतृत्व का महत्व

राजमाता विजया राजे सिंधिया मिलनसार, स्नेही तथा जनसेवी भावना से ओतप्रोत महिला थीं, साथ ही एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थीं। उनकी जनसेवा का प्रभाव देखें उनके नहीं रहने के बाद भी आज भी कई शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सा संस्थान व समाज उपयोगी कार्य अनवरत उनके आशीर्वाद से चल रहे हैं। अपने निजी जीवन में वे बहुत सादगी पसंद थीं। लेकिन कर्मठता पूर्वक कार्य उन्होंने ताउम्र ऐसा किया कि उन्हें नजदीक से जानने वाले उनकी अनथक कार्यशैली को जानने वाले दांतों तले उँगली दबा लेते थे। राजमाता विजयाराजे सिंधिया का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। उनके पिता ठाकुर ठाकुर महेंद्र सिंह ब्रिटिश हुकूमत में डिप्टी कलेक्टर थे। अल्पावस्था से ही अपने नाना नानी के सानिध्य में रहीं, जिनके संस्कारों से अभिभूत राजमाता पर बहुत गहरा असर पड़ा। एक फरवरी 1969 के चुनाव माहौल में जब अटल बिहारी वाजपेई वाराणसी पहुंचे थे तो बेनिया बाग में आमसभा रखी गई थी, जिसमें राजमाता का भी भाषण था। वे जब बोल चुकीं तब बाजपेयी जी भाषण देने खड़े हुए। उनके संबोधन पश्चात प्रथम संवाद के- कहिये सुना आपने राजमाता का भाषण....! कितना ओज है कितनी वेदना है उनके भाषण में! राजनीति के क्षेत्र में है कोई दूसरा, जो इनके साथ तुलना कर सकें। अपने राजमहल के सब सुख छोड़कर वे आज जनता का दुःख बंटाने निकल पड़ी हैं। अटल जी ने भी राजमाता को हमेशा बड़प्पन और सम्मान दिया, उन्होंने तो उनके ऊपर से लेख भी लिखे हैं। राजमाता का आत्मबल काफी ओजता लिये हुये था। वे कोई भी निर्णय लेने और उसे कार्यरूप में परिणित करने में जरा भी नहीं सकुचाती थीं। जनता के हितों के लिये वे किसी भी खतरे का सामना करने के लिये सदा तैयार रहती थीं। जनहित के लिये कितना भी बड़ा त्याग करने के लिए वे तत्पर रहती थीं। इसका एक उदाहरण है। जब ग्वालियर राय का विलय भारतीय गणराय में हुआ तो उस समय उन्होंने कहा कि हमारा राय खत्म हो रहा है जरूर, अपितु जनता के कल्याण के लिये यदि प्रजातंत्र यादा हितकर है तो उसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। जनता के विकास और कल्याण के लिये ही उन्होंने ने राजनीति में कदम रखा। 1965 के आम चुनाव के बाद का मध्य प्रदेश के महाकौशल और विंध्य के क्षेत्र में सूखे के कारण भयंकर अकाल पड़ा था। सो वहां लोगों का जीवन दूभर हो गया था। जिन लोगों की यह जिम्मेदारी थी कि वे ऐसी विकट परिस्थितियों से वहां की जनता को निजात दिलाने का प्रयास करें। उन ऐसे सत्ताधीश भूखेनंगी जनता के समक्ष जाने की बजाय पचमढ़ी की सुरम्य वादियों पर पिकनिक मना रहे थे। तब ऐसी स्थिति को देखकर राजमाता से रहा नहीं गया। और वे अपने स्वास्थ्य और सुखचैन की चिंता किये बगैर उस सूखे और प्रचंड गर्मी में धुंआधार दौरा किया। जहां वे लोगों के बीच जाकर उनके दुःख दर्द को सुनकर उन्हें दिलासा देतीं और जितना मदद करते बन सका वे अपनी क्षमतानुसार उनके दर्द को कम करने का कार्य किया। राजमाता ने कभी भी कुर्सी का मोह नहीं किया। वे चाहतीं तो कभी की मुख्यमंत्री सहित बड़े पदों पर सुशोभित हो सकती थीं। पर उन्होंने जनसेवा में आने, इसे गौण समझा और यही शैली इन्हें जनता में लोकप्रिय और विजय शालिनी बनाने में हमेशा सहायक सिद्ध होता रहा। उन्होंने हमेशा नारी जाति को स्वावलंबी और उनकी शक्ति को महसूस कराने का कार्य किया। 16 मई 1969 को मध्यप्रदेश के विधान सभा चुनाव में तो उज्जैन की नारियों से एक सभा में कहाकि मैं जानती हूं कि महिलाओं में कार्य करने की असीम शक्ति है इसे आवश्यकता इस बात की है कि वे किसी कार्य का संकल्प धारण कर कार्य में जुटें। समानता के प्रचार का उपयोग कर उन्हें देश सेवा में लग जाना चाहिये। ऐसे कठिन काल में जबकि समाज में नैतिकता, चरित्र और धर्म का लोप होने का समय है, महिलाओं को आगे बढ़कर अपनी संस्कृति, धर्म और देश की परम्पराओं की रक्षा करनी चाहिये। राजमाता के जीवन में हिन्दुत्व के प्रबल पोषक और आजादी के प्रतीक महाराणा प्रताप और शिवाजी के चरित्र का गहरा प्रभाव और बहुत कुछ अनुकरणीय भाव परिलक्षित दिखाई देता है। राजमाता ने राजनीति में प्रवेश कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ किया। और सर्वप्रथम उन्होंने 1962 में ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़ा। जिसमें बहुती भारी मतों से विजयी रहीं। इसी वर्ष वज्राघात स्वरूप उनके पति महाराज का भी निधन हो गया। 1966 आते आते उनका कांग्रेस पार्टी में मोहभंग हो गया और उन्होंने जनसंघ पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया। और जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ तो पार्टी को जन्म देने वाले लोगों में प्रमुख रूप से राजमाता भी शामिल थीं।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। उनके पिता ठाकुर ठाकुर महेंद्र सिंह ब्रिटिश हुकूमत में डिप्टी कलेक्टर थे। अल्पावस्था से ही अपने नाना नानी के सानिध्य में रही, जिनके संस्कारों से अभिभूत राजमाता पर बहुत गहरा असर पड़ा। एक फरवरी 1969 के चुनाव माहौल में जब अटल बिहारी वाजपेई वाराणसी पहुंचे थे तो बेनिया बाग में आमसभा रखी गई थी, जिसमें राजमाता का भी भाषण था। वे जब बोल चुकीं तब बाजपेयी जी भाषण देने खड़े हुए। उनके संबोधन पश्चात प्रथम संवाद के- कहिये सुना आपने राजमाता का भाषण...! कितना ओज है कितनी वेदना है उनके भाषण में! रानजीति के क्षेत्र में है कोई दूसरा, जो इनके साथ तुलना कर सकें। अपने राजमहल के सब सुख छोड़कर वे आज जनता का दुःख बंटाने निकल पड़ी हैं। अटल जी ने भी राजमाता को हमेशा बड़प्पन और सम्मान दिया, उन्होंने तो उनके ऊपर से लेख भी लिखे हैं। राजमाता का आत्मबल काफी ओजता लिये हुये था। वे कोई भी निर्णय लेने और उसे कार्यरूप में परिणित करने में जरा भी नहीं सकुचाती थीं। जनता के हितों के लिये वे किसी भी खतरे का सामना करने के लिये सदा तैयार रहती थीं। जनहित के लिये कितना भी बड़ा त्याग करने के लिए वे तत्पर रहती थीं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कन्हा ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। ([illegible])

बजट सत्र से पहले विपक्ष को साधने की तैयारी? किरेन रिजिजू ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली ।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट सत्र से पहले प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा करने के लिए 27 जनवरी को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। यह बैठक संसद के मुख्य समिति कक्ष में होगी और इसमें सत्र का एजेंडा तय किया जाएगा, जो 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा।

बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें एक बार का अवकाश होगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक निर्धारित है, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में 30 बैठकें होंगी, जिसमें केंद्रीय बजट 2026-27 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और रायसभा दोनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए सत्र का औपचारिक उद्घाटन करेंगी। बजट से पहले, वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक्स पर पहले से

घोषित सीमा शुल्क दरों पर प्रकाश डाला। पिछले बजट सत्रों के दौरान, भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र के रूप में मजबूत करने और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक निर्णायक कदम के रूप में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। इस कदम का उद्देश्य वस्तुओं पर लागू उल्टी शुल्क संरचना को ठीक करना था। मंत्रालय ने ओपन सेल और प्रमुख घटकों पर बीसीडी को घटाकर 5 प्रतिशत भी कर दिया था। वित्त मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमारी मेक इन इंडिया नीति के अनुरूप, और उल्टी शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए, मैं इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने और ओपन सेल और अन्य घटकों पर बीसीडी को घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। एलसीडी/एलईडी टीवी के लिए ओपन सेल्स के स्थानीय उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए, ओपन सेल्स के कुछ हिस्सों पर बीसीडी (बैकग्राउंड कंट्रोल) को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है, जो पहले की गई छूटों को आगे बढ़ाता है।

सर्वदलीय बैठक में सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एजेंडा पर चर्चा की जाएगी। पिछले दो सत्रों में, जिनमें 2025 के मानसून और शीतकालीन सत्र शामिल हैं, विपक्षी दलों ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर चर्चा करने की मांग की है, जो पूरे देश में चल रहा है। पिछले सत्र में, कुछ नेताओं ने लाल किले के पास हुए दिल्ली विस्फोट, वायु प्रदूषण और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का आह्वान किया था। अंत में, सरकार ने वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ पर और चुनाव सुधार पर विशेष चर्चा करने का निर्णय लिया।

EWS छात्रों को स्कूल वर्दी खरीदने के लिए दिल्ली सरकार नकद राशि दे सकती है : दिल्ली उच न्यायालय

नई दिल्ली । दिल्ली उच न्यायालय ने निजी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह के अंतर्गत आने वाले छात्रों को वर्दी खरीदने के लिए नकद राशि उपलब्ध कराने के सरकार के फैसले को शुक्रवार को बरकरार रखा। अदालत ने अधिकारियों को वर्दी उपलब्ध कराने के अपने पूर्व निर्देश में संशोधन करते हुए फैसला सुनाया कि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सब्सिडी देने का निर्णय शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के आदेश के विपरीत नहीं है। न्यायालय ने कहा कि इस तरीके से सुनिश्चित होगा कि छात्रों को समय पर वर्दी मिल सके। मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि छात्रों को पर्याप्त राशि समय पर और जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। पीठ ने कहा, निस्संदेह, प्रत्येक छात्र का माप लेना, जीईएम पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के कपड़े के लिए ऑर्डर देना, सामग्री की खरीद के बाद माप के अनुसार वर्दी सिलवाना और अंत में नए सत्र के प्रारंभ से पहले स्कूलों में वर्दी वितरित करना, यह सब एक साथ करना असंभव होगा। पीठ ने कहा, छात्रों को पैसे उपलब्ध कराने के सरकार के निर्णय से यह सुनिश्चित होगा कि समय पर छात्रों को वर्दी मिल जाए। सरकार का यह निर्णय आरटीई अधिनियम और 2011 के नियमों के विपरीत नहीं कहा जा सकता। वर्ष 2011 के नियमों के तहत वर्दी उपलब्ध कराना अनिवार्य है लेकिन नियमों में यह नहीं लिखा है कि सरकार को केवल वस्तु के रूप में ही वर्दी उपलब्ध करानी होगी। अदालत ने दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक पुनर्विचार याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें 13 अप्रैल 2023 को जारी निर्देश में संशोधन की मांग की गई थी। पिछला आदेश गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की याचिका पर आया था, जिसमें सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त किताबें, वर्दी और अन्य अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।

पूर्वी दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, कैफे में युवक की गोली मारकर हत्या; सामने आई ये बड़ी वजह

पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में वेलकम थाना क्षेत्र के मौजपुर स्थित मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे में शुक्रवार रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, देर रात फायरिंग की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को एक युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। उसकी पहचान फैजान उर्फ फजी (24) पुत्र सेहरोज आलम, निवासी जेएमसी वेलकम के रूप में हुई। वहीं, घायल युवक को तत्काल जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह मामला पैसों के लेनदेन से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। आशंका है कि किसी विवाद के चलते युवक को निशाना बनाकर गोली मारी गई। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। डीसीपी उत्तर पूर्व जिला आशीष मिश्रा के अनुसार आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

केरल सरकार शबरिमला से सोना गायब होने के मामलों में जांच को पंगु करने की कोशिश कर रही : कांग्रेस

नई दिल्ली ।

कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने शनिवार को आरोप लगाया कि केरल सरकार शबरिमला से सोना गायब होने के मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) पर दबाव बना रही है ताकि जांच को ''पंगु किया जा सके। वेणुगोपाल ने कोचि में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि सरकार एसआईटी की जांच में कोई प्रगति नहीं होने देने की कोशिश कर रही है। संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के संयोजक अदूर प्रकाश की शबरिमला से सोना गायब होने के मामलों के मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी से मुलाकात की तस्वीरों के बारे में संवाददाताओं द्वारा सवाल पूछे जाने पर अलप्पुझा से सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री की भी उसी व्यक्ति के साथ तस्वीरें हैं। उन्होंने कहा, ''मामलों की जांच कांग्रेस नहीं कर रही। पिनरायी विजयन के अधीन पुलिस यह काम कर रही है इसलिए जब तस्वीरों की जांच की जाएगी तो वे उसके साथ मुख्यमंत्री की तस्वीर की भी जांच कर सकते हैं। वेणुगोपाल ने कहा, ''खैर, हमारा मजबूत और स्पष्ट रुख यह है कि भगवान अयप्पा का सोना चुराने वालों को न तो देवता बख्शेंगे और न ही केरल के लोग। भगवान सब कुछ देख रहा है। इस बीच, केरल प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने आरोप लगाया कि एसआईटी गायब सोने की बरामदगी के पहलू पर ध्यान नहीं दे रहा जबकि केरल उच न्यायालय ने हाल में इसका निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) सोना गायब के होने के मामलों में शामिल अपने नेताओं को बचा रही है। उन्होंने कहा कि 27 जनवरी को राय सचिवालय तथा सभी जिला आयुक्तालयों पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और मामले में उचित जांच की मांग की जाएगी। प्रकाश की पोट्टी से मुलाकात के बारे में जोसेफ ने कहा कि यूडीएफ संयोजक की कभी ऐसी स्थिति नहीं रही कि वह भगवान अयप्पा के मंदिर से सोने के कथित गबन में शामिल लोगों की मदद कर सकें। उन्होंने कन्नूर में संवाददाताओं से कहा कि प्रकाश की पोट्टी के साथ तस्वीर में कुछ भी गलत नहीं है। केपीसीसी प्रमुख ने कहा कि एसआईटी ने प्रकाश से पूछताछ नहीं की है क्योंकि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला जबकि उसने पूर्व देवस्वओम मंत्री के. सुरेंद्रन से पूछताछ की। शबरिमला से सोना गायब होने का मामला मंदिर में द्वारपालक (रक्षक देवता) की मूर्तियों और श्रीकोविल (गर्भगृह) के द्वार की चौखट से सोने के कथित गबन से जुड़ा है। मामले की जांच कर रहे एसआईटी ने पोट्टी और त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड के दो पूर्व अध्यक्षों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है।

उच शिक्षा युवाओं की बड़ी ज़रूरत, सपा जनप्रतिनिधि बेख़बर-दीपक कुमार डब्लू एडवोकेट

पिछले वर्ष सांसद और आज विधायक को दिया ज्ञापन, कार्यवाही से नहीं कराया अवगत

फतेहपुर।

उच शिक्षा युवाओं की बड़ी ज़रूरत है, इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि बेख़बर हैं। महात्मा गाँधी महाविद्यालय में बीएससी आदि विषयों की कक्षाएं संचालित न होने से जनपद के गरीब छात्र उक्त शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कक्षाएं संचालित कराने के लिए पिछले वर्ष सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल को ज्ञापन दिया था। समस्या निदान की बात तो दूर, उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही से भी अवगत नहीं कराया। छात्रों की परेशानी के मद्देनजर आज समाजवादी पार्टी के सदर विधायक चन्द्रप्रकाश लोधी को ज्ञापन दिया है। उम्मीद है कि शायद यही अपने जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभाकर छात्रों की समस्या का निदान करा सकें। उक्त बातें ज्ञापन देने के बाद अभिभावक संघ के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार डब्लू एडवोकेट ने कहा।

उन्होंने कहा कि फतेहपुर जनपद के गरीब छात्रों के लिए उच शिक्षा प्राप्त करना एक गम्भीर समस्या है, क्योंकि जनपद में एक भी सरकारी महाविद्यालय ऐसा नहीं है, जिसमें छात्र बीएससी की पढ़ाई कर सकें। छात्राओं के लिए तो राजकीय महिला महाविद्यालय में व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि सन् 2000 में तत्कालीन सांसद अशोक पटेल ने अपनी निधि से महात्मा गाँधी महाविद्यालय में 22 लाख रुपये की लागत से बीएससी भवन का निर्माण कराया था, लेकिन प्रबन्ध समिति के मनमाने रवैये के कारण 25 वर्ष बाद भी बीएससी की कक्षाएं संचालित नहीं हो सकीं। समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र व भूगोल विषयों की कक्षाएं प्रस्तावित थीं, इनकी कक्षाएं चालू कराने के बजाय एमए राजनीति विज्ञान की संचालित कक्षा भी बन्द करा दी गईं। परिणाम स्वरूप जिले का युवा उच शिक्षा से वंचित हो रहा है।

कहा कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी के ही सदर विधायक चन्द्रप्रकाश लोधी को आज ज्ञापन दिया है। उम्मीद है कि जनपद के गरीब छात्रों के हित में उक्त कक्षाएं संचालित कराने के साथ ही सदर विधायक हिन्दी में संचालित 60-60 स्थानों को बढ़वाने का काम भी करेंगे। ज्ञापन देते समय साथ में रवीन्द्र यादव एडवोकेट आदि रहे।

लोकतंत्र के नाम निकली रैली, मताधिकार के प्रति किया गया जागरूक

देवरिया।

16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शनिवार को जनपद में लोकतांत्रिक चेतना को सशक्त करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज परिसर से जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से आमजन, विशेषकर युवा मतदाताओं को मतदान के महत्व से जोड़ने का प्रयास किया गया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति नागरिक की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। जागरूकता रैली में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, स्काउट-गाइड, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में नागरिक शामिल रहे। प्रतिभागियों ने हाथों में स्लोगन पट्टिकाएं लेकर 'मेरा वोट, मेरी पहचान' और 'पहले मतदान, फिर जलपान' जैसे नारों के जरिए मतदान

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर छात्रों, कार्यकर्तियों और स्वयंसेवकों ने दिया शत-प्रतिशत मतदान का संदेश

का संदेश दिया। रैली जीआईसी से निकलकर कलेक्ट्रेट, पोस्टमार्टम चौराहा और जलकल रोड होते हुए पुनः जीआईसी परिसर में संपन्न हुई। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में नागरिकों को मतदाता शपथ दिलाई गई। नव पंजीकृत मतदाताओं को पहचान पत्र वितरित किए गए, वहीं जागरूकता अभियान में योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नुक्कड़ नाटक ने लोकतांत्रिक भागीदारी का प्रभावी संदेश दिया। आयोजन में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की सहभागिता रही।

हुसैन आहू-ए-काबा सनम कदों का ज़वाल- जाबिर हुसैन सिद्दीकी

हज़ारीबाग।

हज़रत इमाम हुसैन सिब्त -ए- पैगंबर, नवासा-ए-रसूल-ए-खुदा, हज़रत फातिमा-तुज़-ज़हरा की गोद में और अली के आंगन में चार शाबान को मदीना- तुल- मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए। यह विशाल वृक्ष जो (पहले) एक पौधा है, यही पौधा विशाल वृक्ष बनकर पूरी दुनिया में इस्लाम और हक़ानियत (सचाई) की आवाज़ बनकर सायेदार पेड़ की तरह छा गया। इंसानियत की आवाज़ पूरे आलम में बुलंद की, जिसकी धमक आज भी चारों तरफ महसूस हो रही है। इमाम हुसैन ने हज़रत फातिमा- तुज़- ज़हरा सैयदा, ज़ाहिदा, तकिया, ताहिरा की गोद में जन्म लेकर दीन-ए-इस्लाम की जड़ों की जो सिंचाई की है, विश्व का इतिहास उसकी मिसाल पेश करने से असमर्थ है। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत फातिमा ज़हरा के दिल को ठंडक पहुँचाई और रूह-ए- मोहम्मदी को हमेशा के लिए खुश करके यह साबित कर दिया कि नाना जान!

आज जो एक पौधा है, कल वह सायेदार वृक्ष बनकर इस्लाम को हमेशा साया पहुँचाएगा और पूरी दुनिया को यह बता देगा कि बातिल (असत्य) ताकतों से हाथ मिलाना इंसानों का काम नहीं है, बातिल ताकतों से हाथ मिलाना इंसानियत के खिलाफ है। हज़रत इमाम हुसैन ने एक जमात को, एक पूरे कुनबे (परिवार) को हमेशा के लिए यह साबित कर दिया कि तुम गलत हो,

तुम्हारी नीयत गलत है, तुम्हारे तौर-तरीके गलत हैं और जब भी इस्लाम के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद होगी तो वह आवाज़ हमेशा के लिए दबा दी जाएगी, बल्कि आवाज़ उठाने वाले को हमेशा के लिए परास्त कर दिया जाएगा।

यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में न यज़ीद है न यज़ीदियत है, अगर कुछ है तो हुसैन है और हुसैनियत है। फातिमा ज़हरा! आपकी गोद में जलवागर (सुशोभित) होने वाला यह दुधमुंहा बच्चा एक दिन आलम-ए-इस्लाम के लिए मर्दे-गुनीमत और मर्दे-हक़ आगाह साबित होगा, जिसकी वीरता का इतिहास पूरी दुनिया में मानवीय दिलो-दिमाग पर अंकित हो जाएगा और सभी लोग हज़रत इमाम हुसैन के शहादत के इतिहास को याद करते रहेंगे।

इसलिए यह शहादत हमेशा के लिए अगर हुई है तो अपने नफ़्स (स्वार्थ) के लिए नहीं हुई है, हक़ (सत्य) के लिए हुई है, दीन के लिए हुई है, इस्लाम के लिए हुई है। और अगर इस्लाम की आवाज़ पूरी दुनिया में किसी ने बुलंद की है तो वह चार शाबान को पैदा होने वाले हुसैन इब्न अली हैं, सिब्त-ए-पैगंबर हैं, लख़्त-ए-जिगर-ए-फातिमा ज़हरा हैं, जिनकी विलादत (जन्म) मदीना-तुल-मुनव्वरा (मूल पाठ में मक्का लिखा है लेकिन ऐतिहासिक रूप से मदीना है) में चार शाबान-अल- मुअज़्ज़म को हुई और पूरी दुनिया के इंसानों के दिलो-दिमाग में आज भी ज़िंदा हैं और कल भी ज़िंदा रहेंगे।

पूरी दुनिया में उनकी ईमान से भरी दास्तान पढ़ी जाती रहेगी और उनकी कुर्बानी हमेशा याद की जाती रहेगी। खुदा-ए-पाक हज़रत इमाम हुसैन की शिक्षाओं पर हम पूरी दुनिया के मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए,जिसमें इंसानियत है, शराफत है, मोहब्बत है, इखलास (निष्ठा) है, भाईचारा है, पर्दा है, जज़्बा-ए-सरफरोशी है और जज़्बा-ए-हक़ानियत है।

दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर हाइटेक सुरक्षा, एआई स्मार्ट चश्मे और 30000 पुलिसकर्मियों की तैनाती

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 30,000 से अधिक पुलिसकर्मियों और अर्द्धसैनिक बलों की 70 से अधिक कंपनियों को तैनात किया जाएगा. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बल के जवान पहली बार कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) से लैस स्मार्ट चश्मे का इस्तेमाल करेंगे जो चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) और थर्मल इमेजिंग तकनीक से लैस होंगे. भारत में निर्मित यह स्मार्ट चश्मे वास्तविक समय में अपराधियों, संदिग्धों और घोषित अपराधियों के पुलिस डेटाबेस से जुड़े होंगे. इससे जमीनी स्तर पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में व्यक्तियों की तुरंत पहचान करने में मदद मिलेगी. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (नयी दिल्ली) देवेश कुमार महला ने कहा, ''ये पहनने योग्य उपकरण (स्मार्ट चश्मे) पुलिस अधिकारियों द्वारा उपयोग किए

जाने वाले मोबाइल फोन से जुड़ेंगे, जिससे उनकी आपराधिक डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त होगी.'' उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तो स्मार्ट चश्मे पर एक हरा बॉक्स दिखाई देता है, जबकि एक लाल बॉक्स आपराधिक रिकॉर्ड का संकेत देगा. गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली परेड के लिए सुरक्षा व्यवस्था में बहुस्तरीय अवरोधक लगाए गए हैं और इसके अलावा छह स्तरों की जांच एवं तलाशी शामिल है. नयी दिल्ली में एफआरएस सहित हजारों सीसीटीवी लगाए गए हैं.

दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार

एफआरएस से लैस मोबाइल वाहनों को भी विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाएगा. महला ने कहा, ''दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है.'' उन्होंने कहा कि कई सुरक्षा एजेंसियों के साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है. कुल तैनाती में से 10,000 सुरक्षाकर्मियों को विशेष रूप से नयी दिल्ली में तैनात किया जाएगा.

पुलिस अधिकारी हाई अलर्ट पर रहेंगे

दिल्ली के सभी जिलों के डीसीपी को सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी हाई अलर्ट पर रहेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देंगे. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि नयी दिल्ली, उत्तरी और मध्य जिलों में लगभग 4,000 स्थानों पर छह सुरक्षा चौकियों की पहचान की गई है. परेड मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 500 उच्च-रिजॉल्यूशन एआई कैमरे लगाए जा रहे हैं. गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले सभी लोगों को सुरक्षा स्टिकर दिए जाएंगे.

भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बढ़ाई सतर्कता

पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) ने परेड मार्ग सर्वेक्षण और अन्य जांच पूरी कर ली है. बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और लोकप्रिय बाजारों जैसे अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

विकास के हर पैमाने पर उत्तर प्रदेश को शीर्ष बनाने का लें संकल्प- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को 'उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राय के लोगों से आह्वान किया कि वे विकास के हर पैमाने पर राय को शीर्ष बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश दिवस की बधाई दी। योगी ने मोदी के पत्र को 'एक्स पर साझा करते हुए लिखा, ''उत्तर प्रदेश दिवस के पावन अवसर पर आत्मीय एवं प्रेरणादायी शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हृदय से आभार। मोदी ने पत्र में लिखा, ''आज का यह दिन उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए संकल्प का भी अवसर है। उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को विकास के हर पैमाने पर राय को शीर्ष बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा। मोदी ने उत्तर प्रदेश के लोगों से यह संकल्प लेने का आह्वान किया कि वे राय को आत्मनिर्भर अभियान, मिशन विनिर्माण एवं हरित ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बनाएंगे। उन्होंने कहा, ''जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राय है और जब हम सामूहिक शक्ति से विकास का निर्धारित लक्ष्य लेकर चलेंगे तो उत्तर प्रदेश की प्रगति से देश के विकास को भी नयी गति मिलेगी।

मोदी ने ''उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य और प्रदेशवासियों के समर्पण को नमन करते हुए कहा, ''विकसित प्रदेश का यह संकल्प विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की दिन-प्रतिदिन ऊर्जा बनेगा। प्रधानमंत्री ने राय के निवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, ''मैं काशी का सांसद हूं और उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुझे चुनकर लोकसभा भेजा है, इसलिए यह दिन मेरे लिए और भी विशेष हो जाता है। उत्तर प्रदेश के लोगों से मुझे जो प्रेम और आत्मीयता मिली है, वह मेरे लिए

बहुत बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ खास है, राय ने हमेशा अपने सामर्थ्य से एवं अपनी प्रतिभा से देश के विकास को गति दी है। उन्होंने कहा, ''मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज 'विकास भी और विरासत भी के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। मोदी ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों की चर्चा करते हुए आजादी की लड़ाई के वीर शहीदों को भी स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक समय ऐसा भी था जब दशकों तक परियोजनाओं के लंबित रहने के कारण आम लोगों के मन में व्यवस्था के प्रति एक अविश्वास पैदा हो गया था लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार में पुरानी परियोजनाओं के साथ-साथ नयी परियोजनाएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं तथा इसमें केंद्रीय स्तर पर होने वाली प्रगति बैठकों की भी अहम भूमिका रही है। मोदी ने राय की कानून-व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा, ''उत्तर प्रदेश आज मजबूत कानून व्यवस्था का भी एक उदाहरण बन चुका है। नए कीर्तिमानों के साथ राय ने जन सेवा और लोक कल्याणकारी नीतियों को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाकर उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए रिकॉर्ड संख्या में बने नए घरों से लेकर बेहतर जीवन के लिए उन तक पहुंच रहे विभिन्न सुविधाएं अंतोदय के लिए भाजपा के समर्पण को दिखाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पिछड़ों को प्राथमिकता देने के मंत्र को भी आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ''मुझे याद है कि मैंने गरीब महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली उज्ज्वला योजना को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू किया था और आज उज्ज्वला योजना गरीब कल्याण एवं महिला सशक्तीकरण का पर्याय बन चुकी है। आज का यह दिन उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए संकल्प का भी अवसर है।

2027 में भी बने यूपी में डबल इंजन की सरकार - शाह

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर यूपी महोत्सव का आगाज हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में भाग लेने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे। यूपी दिवस समारोह का आयोजन 24-26 जनवरी तक हो रहा है। यूपी दिवस समारोह का उद्घाटन अमित शाह ने किया। इससे पहले एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक और अन्य नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने यूपी चुनाव 2027 का शंखनाद कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल से यूपी चुनाव 2027 को लेकर भाजपा के अभियान का आगाज एक प्रकार से कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस मंच से प्रदेश के लोगों से 2027 में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आह्वान करता हूं। साथ ही, सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की उन्होंने जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी और प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ शानदार काम कर रहे हैं। यूपी विकास की राह पर बढ़ रहा है। प्रदेश में लगातार विकास कार्यों को गति दी गई है। एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट तक के निर्माण हो रहे हैं। जल्द ही प्रदेश पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राय बन जाएगा। अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में पांच शताब्दियों के बाद भव्य श्रीराम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शानदार आयोजन कराया गया। यूपी वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के निर्माण का हब बनकर उभरा है। 2017 के पहले कोई इन बातों की कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज यूपी ग्रीन डेस्टिनेशन बन गया है। प्रदेश में 15 लाख करोड़ की योजना जमीन पर उतार गया है। डकैती और लूट की घटनाओं में कमी आई है। अमित शाह ने कहा कि प्रदेश की इंटरनेशनल सीमा को भी सुरक्षित किया गया है। यूपी विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में देशभक्ति की लौ जागृत हो चुकी है। अगला साल चुनाव का साल है। यूपी के विकास के लिए प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियां यूपी का कल्याण नहीं कर सकती हैं। भाजपा ही कर सकती है। हमने भ्रष्टाचार समाप्त किया है।

शंकराचार्य विवाद पर मायावती की सियासी एंट्री, योगी सरकार को दी बड़ी चेतावनी

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को धर्म और राजनीति को अलग रखने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि इनके बढ़ते दखल से विवाद, तनाव और सामाजिक अशांति पैदा हो रही है। उनकी ये टिप्पणी प्रयागराज में माघ मेले को लेकर चल रहे विवाद और शंकराचार्य को संगम में स्नान करने से रोके जाने के आरोपों के बीच आई है। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक पोस्ट में मायावती ने कहा कि हाल के वर्षों में न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में धार्मिक त्योहारों, छुट्टियों, पूजा-पाठ और स्नान समारोहों में राजनीतिक हस्तियों का हस्तक्षेप बढ़ा है।

मायावती ने कहा कि यह प्रवृत्ति जनता के बीच नए संघर्षों और चिंताओं को जन्म दे रही है। प्रयागराज स्नान समारोह विवाद को एक ताजा उदाहरण बताते हुए मायावती ने चेतावनी दी कि संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए धर्म को राजनीति से जोड़ना अंतर्निहित रूप से खतरनाक है। बीएसपी प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि देश का संविधान और कानून स्पष्ट रूप से राजनीति को धर्म से और धर्म को राजनीति से दूर रखने की परिकल्पना करते हैं, जबकि जन कल्याण और जन-केंद्रित शासन को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं भी दीं।

उनकी ये टिप्पणियां माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को संगम में स्नान करने से कथित रूप से रोके जाने को लेकर चल रही तीखी राजनीतिक बयानबाजी के बीच आई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार पर सनातन धर्म की परंपराओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि संत और ऋषि गौरव का स्रोत हैं और प्रमुख धार्मिक आयोजनों के दौरान उनसे मिलकर आशीर्वाद लेना धार्मिक परंपरा का अभिन्न अंग है।

एसआईआर में भगवानदास के घर मो. अफजल रह रहे

अखिलेश बोले- कालनेमि की बात करने वालों का काल बनकर आएगा कालनेमि

लखनऊ ।

राजधानी लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा भाजपा की कंपनी को वोटर लिस्ट का काम आउटसोर्स किया गया है। तंज कसा कि जारी की गई वोटर लिस्ट में भगवानदास के घर में मोहम्मद अफजल है। वोटर लिस्ट सेकुलर हो रही है। लगता है बीजेपीवालों ने जानबूझकर मजाक किया है।

सपा मुखिया शनिवार को समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2022 के बाई इलेक्शन में पूरा का पूरा बूथ लूटा गया। पुलिस ने अपने कपड़े बदलकर वोट डाले। एसआईआर में बार-बार समय बढ़ाया गया। इसका मतलब सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि जिन्हें नोटिस दिया जा रहा है, उसकी जानकारी चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं दे रहा है चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। वह सरकार से मिला हुआ है। अधिकारी सरकार से मिलकर गड़बड़ कर रहे हैं। पहले कहा गया था कि मैपिंग मतदाताओं को नोटिस नहीं दिया जाएगा। अब 3 करोड़ से अधिक लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। सीएम योगी के कालनेमि के बयान पर सपा मुखिया ने कहा कि कालनेमि को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमि कौन हैं। कालनेमि ही इनका काल बनकर आएगा। केजीएमयू से मजार हटाने के सवाल पर कहा कि सरकार को केजीएमयू भी हटवा देना चाहिए, क्योंकि इसे क्रिश्चियन ने बनाया था।

तमिलनाडु के राज्यपाल ने विधानसभा में अभिभाषण न पढ़कर अपने पद का अपमान किया- स्टालिन

नई दिल्ली । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्यपाल आर. एन. रवि ने विधानसभा सत्र के प्रारंभ में अभिभाषण न पढ़कर अपने पद का ''अपमान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ''पहले के राज्यपाल आर. एन. रवि जैसे नहीं थे और मुझे उनकी आलोचना करने पर विवश होना पड़ रहा है। स्टालिन ने विधानसभा में कहा, मैं ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहा हूं जो पूर्व मुख्यमंत्रियों सी. एन. अन्नादुरई, एम. करुणानिधि, एम. जी. रामचंद्रन और जे. जयललिता के कार्यकाल में नहीं देखी गईं राज्यपाल (रवि) विधानसभा सत्र की शुरुआत में अभिभाषण न पढ़कर और सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रगान बजाने पर जोर देकर अपने पद का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा में हमेशा राज्यपाल के अभिभाषण के समापन पर राष्ट्रगान बजाया जाता है और सत्र की शुरुआत में तमिल थाई वजथु (तमिल माता की स्तुति) बजाया जाता था। स्टालिन ने कहा, देशभक्ति में हम किसी से कम नहीं है और किसी को जरूरत नहीं है कि वह हमें इसके बारे में समझाए। चुनौतियों का सामना करना मेरे लिए कोई नयी बात नहीं है और मैंने कई चुनौतियों को पार किया है। राज्य में अपराध के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) शासन में आपराधिक घटनाएं पहले के अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) शासन की तुलना में कम हैं।

सरकारी भर्ती की सुपरफास्ट रफ्तार! पीएम मोदी ने एक क्लिक पर बांटे 61,000 अपॉइंटमेंट लेटर

नई दिल्ली ।

पीएम मोदी ने आज देश के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस रोजगार मेले में पीएम ने नवनियुक्त युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह केवल एक नौकरी का पत्र नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का एक निमंत्रण पत्र है।

युवा शक्ति और ग्लोबल हब बनता भारत

संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में शुमार है।

उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण भारत अब डिजिटल मीडिया, एनिमेशन और क्रिएटर इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में एक ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने विदेशों के साथ हो रहे ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे ये समझौते भारतीय युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए द्वार खोल रहे हैं।

तकनीक और नागरिक देवो भव- का मंत्र

पीएम मोदी ने बदलते समय के साथ खुद को अपग्रेड करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए बने iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की सफलता की सराहना की, जिससे अब तक करीब 1.5 करोड़ कर्मचारी जुड़ चुके हैं। उन्होंने नए नियुक्त अधिकारियों को नागरिक देवो भव का मंत्र देते हुए सेवा भाव से काम करने की सलाह दी।

महिला सशक्तिकरण और रिफॉर्म एक्सप्रेस

प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इस बार 8,000 से यादा बेटियों को सरकारी सेवा में प्रवेश मिला है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी लगभग दोगुनी हो गई है। देश की प्रगति को रिफॉर्म एक्सप्रेस बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य जीवन और व्यापार दोनों को आसान बनाना है।

मुंबई का मेयर कौन बीजेपी-शिंदे कैंप में भारी कन्फ्यूजन, बीएमसी के चुनाव पर सस्पेंस गहराया

मुंबई । मुंबई में होने वाले मेयर चुनाव में आखिरी समय में देरी हो गई है। 31 जनवरी के बजाय अब ये चुनाव फरवरी की शुरुआत में होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को समूह पंजीकरण में आ रही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस अड़चन से बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के नेतृत्व की दौड़ भी रुक गई है, जिससे भारत के सबसे धनी नगर निकाय में सत्ता-साझाकरण को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। महापौर पद के लिए आरक्षण घोषित होने के बाद, बीएमसी ने 31 जनवरी को मतदान की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि, प्रक्रिया में एक बाधा आ गई। भाजपा और शिंदे शिवसेना के पार्षदों ने अपने समूह पंजीकरण को अंतिम रूप नहीं दिया, जिससे चुनावी औपचारिकताएं रुक गईं। जब तक सभी गुट नगर सचिव के कार्यालय में प्रमाण पत्र जमा नहीं कर देते, तब तक महापौर चुनाव आगे नहीं बढ़ सकता। उद्धव की शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस - जिनके संयुक्त रूप से 65 पार्षद हैं - ने तेजी से पंजीकरण पूरा कर लिया, जिससे वे प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल गए। सूत्रों के मुताबिक, अब चुनाव फरवरी के पहले सप्ताह में होने की संभावना है, जिससे कागजी कार्रवाई के लिए समय मिल जाएगा। भाजपा और शिंदे सेना के बीच अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है क्या वे संयुक्त गठबंधन बनाएंगे या अलग-अलग इस फैसले से 227 सदस्यीय विधानसभा में महापौर पद पर नियंत्रण बदल सकता है। इस देरी से महाराष्ट्र की नगर निगम चुनावों के बाद की खंडित राजनीति की झलक मिलती है, जहां गठबंधन समयसीमा से भी तेजी से बदलते हैं। भाजपा-शिव सेना (शिंदे) वर्चस्व की तलाश में हैं, लेकिन प्रक्रियात्मक अड़चनें समन्वय की समस्याओं को उजागर करती हैं।

पंजाब में रेल पटरी क्षतिग्रस्त, विस्फोट के पहलू की जांच कर रही पुलिस

फतेहगढ़ ।

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में सरहिंद के पास मालगाड़ियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेल पटरी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त पाया गया है और पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या यह किसी विस्फोट के कारण हुआ है। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सरहिंद स्टेशन से चार-पांच किलोमीटर दूर खानपुर गांव के पास स्थित यह पटरी शुक्रवार रात क्षतिग्रस्त मिली। उन्होंने कहा कि इस पटरी का इस्तेमाल केवल मालगाड़ियों के लिए किया जाता है। यह पूछे जाने पर कि क्या यह पटरी किसी विस्फोट के कारण क्षतिग्रस्त हुई, अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और पुलिस दल ने घटनास्थल का दौरा किया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में रेलवे अधिनियम की धारा 150 (ट्रेन को जानबूझकर से पटरी से उतारना या उतारने का प्रयास करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बीमारू से देश का विकास का इंजन बना उत्तर प्रदेश- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि राय बीमारू से भारत के विकास का इंजन बनकर उभरा है। उन्होंने राय की अपार क्षमता और संघर्षों एवं नीतिगत उपेक्षा से मुक्ति पाने की यात्रा पर प्रकाश डाला। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि बीमारू भारत के ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रायों - बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश - का संक्षिप्त नाम है। 1980 के दशक में जनसांख्यिकीविद् आशीष बोस ने इन रायों के खराब आर्थिक और सामाजिक संकेतकों, जैसे उच्च गरीबी, निरक्षरता और जनसंख्या

वृद्धि, जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करते हैं, को उजागर करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था।

हालांकि, बेहतर कानून व्यवस्था, पारदर्शी शासन और अवसंरचना विकास के कारण उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव आया है। सेमीकंडक्टर, रक्षा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश के साथ उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे एक्सप्रेसवे ने कनेक्टिविटी में सुधार किया है, जबकि मेट्रो विस्तार और नए हवाई अड्डों ने शहरी परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा दिया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना जैसी पहलों के तहत स्टार्टअप और उद्यमिता को समर्थन मिलने से 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और समाजवादी पेंशन योजना जैसी पहलों से जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अयोध्या, काशी और मथुरा वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र बन गए हैं, जो उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संस्कृति, साहित्य, संगीत और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक जागृति का श्रेय अयोध्या, काशी और ब्रजधाम को दिया।